भवन निर्माण, पेय जल और गन्दी बस्ती हटाने जैसी राष्ट्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नई योजनाएं बनाना

7600. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भवन निर्माण, पेय जल और गंदी बस्ती हटाने जैसी राष्ट्रीय योजनाओं का बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन करने के लिये एक योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकारों को सहायता देने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ). आवास, जलपूर्ति की व्यवस्था करना और गन्दी बस्ती सुधार, राज्य क्षेत्र में है और इस प्रयोजन के लिये राज्य प्लानों में निधियों की व्यवस्था की जाती है । तथापि, पता लगाये गये समस्याग्रस्त गांवों में पीने का पानी मुहैया करने के लिये और 1971 की जनगणना के अनुसार एक लाख की जनसंख्या तक छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों का विकास करने के लिये राज्य सरकारों के संसाधनों को बढाने के लिये, केन्द्रीय सरकार कन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत सहायता दे रही है अर्थात् :–

1. त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम

2. छोटे और मध्यम दर्जे के कस्बों की एकीकृत विकास योजना ।

त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम जिसे 1977–78 में पुन: आरम्भ किया गया था, के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार पता लगाये गये समस्याग्रस्त ग्रामों में जलपूर्ति मुहैया करने के लिये राज्य सरकारों को सहायता अनुदान देती है । छठी योजना 1980–85 के दौरान, इस योजना के लिये 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । वर्ष 1980–81 और 1981–82 के दौरान राज्यवार नियतन का एक विवरण (अनुलग्नक-1) सभा पटल पर रखा जाता है [ग्रंथालय में रखा गया देखिए सख्या एल टी 3891/82]

छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत, छोटे और मध्यम दर्जे के कस्बों के विकास राज्य सरकारों सघ राज्य क्षेत्रों को विकास की चुनिन्दा मदों के लिये समान आधार पर केन्द्रीय ऋण सहायता दी जाती है । 31–3–1982 से, देश में 200 कस्बों को लाभान्वित करने के लिये 2327.39 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है । स्वीकृत राज्यवार राशि का एक विवरण (अनुलग्नक-2) सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० --3891 '82) ।

Financial Assistance to Rajasthan for Development of Desert National Park

7601. SHRI KRISHAN KUMAR GOYAL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government intend to extend financial assistance to Rajasthan

for the development of the desert national park and a research centre on wild-life;

(b) whether any steps have been taken to preserve flora and fauna found in the desert;

(c) whether Government are aware that the desert wild-life species—the black buck, Indian Gazette and the great Indian Bustard are fast vanishing; and

(d) if so, the steps taken to preserve the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICUTURE AND RURAL DEVELOPENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) The Desert National Park in parts of Barmer and Jaisalmer districts of Rajasthan is already being assisted under the Desert Development Programme. An outlay of Rs. 39.54 lakhs was approved during 1981-82. Expenditure under the programme is shared equally between the Union and the State Governments.

(b) Fauna and flora of the desert covered under the Wild Life (Protection) Act, 1972, are getting protection under this law. In the Desert National Park total protection is provided.

(c) an d(d). These species are in Schedule I of the Wild Life (Protection) Act, 1972, and are thus, under full legal protection. It is not correct that these species are fast Vanishing. As a result of conservation action in recent years. their numbers appear to be on the increase.

बादली, दिल्ली में भूमि का अधिग्रहण

7602. **श्री हरीश रावत** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बादली गांव के भूमिहीन हरिजन श्रमिकों को 1975–76 में कितनी भूमि आबंटित की गई थी ;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली के भूमि अधिग्रहण आयुक्त द्वारा इस भूमि का दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिये बिना किसी मुआवजे का भुगतान किये, अधिग्रहण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो भूमि के इस अवैध अधिग्रहण को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Strengthening Community Development Blocks in States

7603. SHRI HARISH RAWAT: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have stressed the need for strengthening Community Development Blocks in the States;

(b) if so, what amount Central Government propose to meet the cost for strengthening the blocks; and

(c) by when this scheme is likely to be brought about?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI BALESHWAR RAM): (a) Yes, Sir.

(b) 50 per cent of the cost of additional staff will be met by the Government of India.

(c) Proposals for strengthening of block administration have already been approved for 11 States|Union Territories.

Targets of Foodgrain Procurement

7604. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR:
SHRI MADHAVRAO SCINDIA:
SHRI T. R. SHAMANNA:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what were the targets of procurement of the food grains for the